

भारतीय विदेश नीति में मध्यपूर्व का आयाम

Middle East Dimension in Indian Foreign Policy

Paper Submission: 12/08/2020, Date of Acceptance: 26/08/2020, Date of Publication: 27/08/2020



दिव्या
शोधार्थी,
राजनीति विज्ञान विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर, राजस्थान, भारत

सारांश

भारत की विदेश नीति में मध्यपूर्व का आयाम भारत और पश्चिम एशिया सम्बन्धों की शुरुआत शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद हुई। भारत के एक बड़े और महत्वपूर्ण साझीदार सोवियत रूस के विघटन ने भारत को विश्व की नयी महाशक्ति अमेरिका से सम्बन्ध बढ़ाने का अवसर प्रदान किया। भारत की राज्यकेन्द्रित अर्थव्यवस्था अब विश्व की उभरती हुई प्रवृत्तियों उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण के कारण पूरे विश्व के बाजार के लिए खुल गयी थी। भारत को आर्थिक आवश्यकताओं के मद्देनजर न केवल मध्यपूर्व को एक तेल आयाम के स्रोत के रूप में ही विकसित करना था बल्कि भारतीय श्रम के बाजार के रूप में भी पश्चिम एशिया बहुत महत्वपूर्ण होने वाला था। सउदी अरब, कतर, ईरान भारत के महत्वपूर्ण हाइड्रोकार्बन निर्यातक देश रहे हैं। तेल उद्योग में आये उछाल के बाद भारत से लाखों की संख्या में कुशल व अकुशल मजदूरों की रोजगार स्थली के रूप में खाड़ी देश सबसे महत्वपूर्ण बन गये।

Middle East Dimensions in India's Foreign Policy India and West Asia relations began after the end of the Cold War. The disintegration of Soviet Russia, a large and important partner of India, gave India an opportunity to increase relations with America, the world's new superpower. India's state-centric economy was now open to the entire world market due to the emerging trends of the world, liberalization, globalization, privatization. India had to develop not only the Middle East as a source of oil imports in view of economic needs but also West Asia was also going to be very important as an Indian labor market. Saudi Arabia, Qatar, Iran have been important hydrocarbon exporting countries of India. After the boom in the oil industry, Gulf countries became the most important as a place of employment of millions of skilled and unskilled laborers from India.

मुख्य शब्द : गुटनिरपेक्षता, अर्थशास्त्र, विदेश नीति, उदारीकरण गुजराल सिद्धान्त, लुक ईस्ट पॉलिसी, कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी, लुक वेस्ट पॉलिसी, एक्सटेंडेड नेबर हुड पॉलिसी, रेमिटेंस, शीतयुद्ध One Belt One Road, China Pakistan Economic Corridor, Joint Comprehensive Plan of Action.

Non-Aligned, Economics, Foreign Policy, Liberalization Gujral Doctrine, Look East Policy, Connect Central Asia Policy, Look West Policy, Extended Neighbor Hood Policy, Remittance, Cold War.

प्रस्तावना

भारत की विदेश नीति में पड़ौसी राष्ट्रों और उनसे सम्बन्धों का प्राचीनकाल से बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। चाणक्य की अर्थशास्त्र हो, मनु की मनुस्मृति या फिर शुक्राचार्य की शुक्र संहिता सभी में विदेश सम्बन्धों का पृथक् से अध्याय रहा है। पड़ौसी देश से सम्बन्ध हों, उनके पड़ौसी से कैसे सम्बन्ध कैसे हों, पड़ौसी के पड़ौसी से सम्बन्धों को किस तरह राष्ट्रहित में उपयोग किया जाये, यह इन तीनों ग्रंथों में भली-भांति वर्णित किया गया है और इसका वास्तविकता में उपयोग सम्राट चन्द्रगुप्त ने किया तथा समय-समय पर भारतीय राजाओं ने इनका लाभ लेकर भारतवर्ष की ख्याति विश्वस्तर तक पहुँचायी।¹

मध्यकाल के अंधकार वाले युग के पश्चात् अंग्रेजों के शासन की 200 साल की गुलामी से आजाद भारत की विदेश नीति आवश्यकता एवं आदर्श के दौराहे पर खड़ी थी। आवश्यकता थी सदियों की आर्थिक व राजनीतिक गुलामी से जकड़े देश को विकास की दिशा देना और आदर्श थे किसी पक्ष में ना जाकर गुटनिरपेक्षता की पालना करना। भले ही गुटनिरपेक्षता को भारतीय विदेश नीति

अक्षरशः नहीं निभा पायी लेकिन आवश्यकता एवं आदर्श का सामंजस्य भली—भाति बिठा लिया गया²

वर्ष 1991 के उदारीकरण के दौर के बाद भारत एक आर्थिक महाशक्ति के तौर पर उभरकर सामने आया और इसी के साथ भारतीय विदेश नीति को अपने आदर्शों को पूरी तरह धरातल पर उतार पाने का मौका भी मिलने लगा। गुजराल सिद्धान्त, लुक ईस्ट पॉलिसी, कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी, लुक वेस्ट पॉलिसी, एक्सटेंडेड नेबर हुड पॉलिसी जैसे नवाचार कर पाने का अवसर व सफल क्रियान्वयन हो पाया। 21वीं सदी में भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था (PPP) के आधार पर बना। भारत की इस प्रगति में भारत के मध्यपूर्व एशिया में सबसे वाले और कार्य करने वाले अप्रवासियों का योगदान अमूल्य है। भारत लगातार कई वर्षों से विश्व में सबसे ज्यादा रेमिटेंस पाने वाला देश बना हुआ है जिसका बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय अप्रवासियों की आबादी मूल देश की आबादी का 25 से 30 प्रतिशत तक है। ऐसे में भारत सरकार का कर्तव्य बनता था कि वे भारतीय अप्रवासियों की बेहतरी, पश्चिमी एशियाई देशों से सम्बन्धों में बेहतरी को अपनी प्राथमिकता बनाये और इसी आवश्यकता को कार्यवाही का आधार बनाकर भारत सरकार ने अपनी लुक वेस्ट पॉलिसी को लिंक वेस्ट पॉलिसी में बदलने का निर्णय किया है।³

भारत सरकार ने लुक ईस्ट को लिंक ईस्ट में बदला और इसी तर्ज पर लुक वेस्ट को बदलकर लिंक वेस्ट का नया नाम दिया गया। भारत के प्रधानमंत्री के लगातार खाड़ी देशों के दौरे, खाड़ी देशों के राष्ट्राध्यक्षों के भारत दौरे इसके पुख्ता प्रमाण हैं। भारतीय अप्रवासियों के लिए विदेश मंत्रालय में स्वतन्त्र प्रभाग का गठन, सोशल मीडिया से प्राप्त शिकायतों एवं सुझावों पर तुरंत कार्यवाही, खाड़ी देशों में मंदिरों, गुरुद्वारों के लिए वहाँ की सरकारों का आगे आगा पश्चिम एशिया के भारत के साथ जुड़ने की कड़ी में नये आयाम हैं।⁴

भारतीय विदेश नीति को पश्चिम एशिया के सम्बन्ध में प्रधानमंत्री मोदी से पूर्व और मोदी के कार्यकाल में बांटकर देख सकते हैं। भारत और पश्चिम एशिया सम्बन्धों की शुरुआत शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद हुई। भारत के एक बड़े और महत्वपूर्ण साझेदार सोवियत रूस के विघटन ने भारत को विश्व की नयी महाशक्ति अमेरिका से सम्बन्ध बढ़ाने का अवसर प्रदान किया। भारत की राज्यकेन्द्रित अर्थव्यवस्था अब विश्व की उभरती हुई प्रवृत्तियों उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण के कारण पूरे विश्व के बाजार के लिए खुल गयी थी।⁵

भारत को आर्थिक आवश्यकताओं के मद्देनजर न केवल मध्यपूर्व को एक तेल आयात के स्रोत के रूप में ही विकसित करना था बल्कि भारतीय श्रम के बाजार के रूप में भी पश्चिम एशिया बहुत महत्वपूर्ण होने वाला था। सउदी अरब, कतर, ईरान भारत के महत्वपूर्ण हाइड्रोकार्बन निर्यातक देश रहे हैं। तेल उद्योग में आये उछाल के बाद भारत से लाखों की संख्या में कुशल व अकुशल मजदूरों की रोजगार स्थली के रूप में खाड़ी देश सबसे महत्वपूर्ण बन गये। उस समय भारत के दाक्षिणी राज्यों से कामगारों

का बहाव पश्चिम एशिया की ओर हुआ जिनमें केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के निवासी ज्यादा थे। ज्यादातर लोग निर्माण जैसे कम आय वाले कार्यों में लगे और थोड़े बहुत व्हाइट कॉलर जॉब पर रुके। इस तरह लगातार बढ़ती भारतीय प्रवासियों की संख्या के कारण भारत सरकार ने 2019 में प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षार्थ अप्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय की स्थापना की। अरब देशों में रहने वाले भारतीयों की आबादी लगभग 1 करोड़ के आसपास पहुँच चुकी है। इन्हीं अप्रवासियों के घर भेजे गये पैसे की बदौलत भारत लगातार 5 सालों से विश्व में सबसे ज्यादा रेमिटेंस पाने वाला देश बना हुआ है। वर्ष 2004 में भारत का रेमिटेंस 78 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया जो कि अब तक का कीर्तिमान है।⁶

समय के साथ भारतीय विदेश नीति के रणनीतिकारों को आभास हुआ कि भारत के ये पश्चिमी एशियाई पड़ोसी भारत को केवल तेल ही नहीं बल्कि इस तेल से पैदा हुई सम्पत्ति भी भेज सकते हैं, तब भारत में पश्चिम एशियाई देशों का निवेशकों के रूप में प्रवेश हुआ। भारत के इन्हीं निहित हितों की वजह से भारत के पश्चिम एशियाई देशों के साथ सम्बन्ध अनेक प्रकार से प्रभावित होते रहे। भारत ने पश्चिम एशिया में जैसमीन क्रांति के बाद आये जबरन सत्ता परिवर्तन अंदोलनों का विरोध किया और बाह्य हस्तक्षेप का कड़ा विरोध किया। इस दौर में भारत का नजरिया पश्चिम को देखने भर तक सीमित था जबकि जरूरत पश्चिम से तारतम्य बिठाने की थी। भारत की मध्यपूर्व नीति को नयी धार और नयी दिशा नरेन्द्र मोदी के प्रथम कार्यकाल की शुरुआत के साथ 2014 में मिली। भारत सरकार ने कोई नया रास्ता, नयी नीति बनाने के बजाय पूर्व में स्थापित लुक वेस्ट की मान्यताओं को समय की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप डालकर नये ढाँचे में डालकर लिंक वेस्ट के रूप में नया और अधिक ऊर्जावान रूप प्रदान कर दिया। इस लिंक वेस्ट की नीति के तीन मूलाधार बनाये गये—

1. अरब खाड़ी देश
2. इजरायल
3. ईरान

भारत के इस मूलाधार के प्रथम बिंदु अरब खाड़ी देशों से सम्बन्ध 1970 के दशक की तेल की खोज के साथ ही नये सांचे में उभर चुके थे। इसकी तुलना में ईरान और इजरायल से भारत के सम्बन्ध ज्यादा नवीन हैं और मुख्यतः 1990 के दशक के बाद उभरकर सामने आ पाये हैं।⁷

इजरायल के साथ भारत के सम्बन्ध ऐतिहासिक रूप से ठंडे रहे हैं। भारत का रुख आजादी के बाद से ही अरब देशों एवं फलीरतीन स्वतन्त्रता सेनानियों का समर्थन कर रहा है। इस रुख के लिए भारत की घरेलू परिस्थितियाँ एक हद तक जिम्मेदार हैं। इन घरेलू कारकों में जम्मू-कश्मीर के मसले पर मध्यपूर्व की चुप्पी और भारतीय वोटबैंक की राजनीति के रूप में भारतीय मुसलमानों का समर्थन पाने के लिए प्रयास शामिल हैं, लेकिन समयांतर में अब ये कारक अपना महत्व खो चुके हैं।⁸

मध्यपूर्व के देशों के संगठन ओ.आई.सी. ने भारत के जम्मू कश्मीर पर कई बार नकारात्मक रूख दर्शाया जबकि इजरायल हमेशा भारत के समर्थन में रहा है। भारत इजरायल का व्यापार लगातार बढ़ रहा है और रक्षा, प्रतिरक्षा, कृषि के क्षेत्र में लगातार नये रास्ते खुल रहे हैं। वर्ष 2017 में मोदी प्रथम प्रधानमंत्री बने जो इजरायल यात्रा पर गये, इससे भारत के फलीस्तीन पर रूख के कारण इजरायल से परहेज की नीति को विराम मिला, साथ ही 2018 के अंत में ओमान और यूएई. में इजरायली नेताओं के स्वागत ने मध्यपूर्व को अलग दिशा प्रदान की।⁹

इजरायल के अलावा ईरान से भारत के सम्बन्ध अर्थव्यवस्था व राष्ट्रीय सुरक्षा के कोण पर आधारित हैं। भारत के मुख्य ऊर्जा निर्यातक के साथ भारत के मध्य एशिया तक रास्ते के 'की पाइट' के रूप में ईरान महत्वपूर्ण रहा है। चीन के बढ़ते प्रभाव, पाकिस्तान के आतंकवाद की रणनीति के कारण भारत के लिए भारत के लिए ईरान की भूमिका महत्वपूर्ण है तभी अमरीकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने ईरान से व्यापार लगातार जारी रखा गया चाबहार बंदरगाह भारत ईरान सम्बन्धों की मिसाल है। इन प्रयासों और सफलताओं के बावजूद भारत के लिंक वेस्ट के प्रयासों में कुछ बाधाएँ हैं।¹⁰ प्रथम तो इजरायल और अरब देशों की फलीस्तीन पर किसी भी घटना के बाद प्रतिक्रिया बदलने से क्षेत्र में अस्थिरता का बड़ा खतरा है। अब तक हुए अरब और इजराइल संघर्षों का इतिहास देखने पर पता चलता है कि यह क्षेत्र एक बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है और इस बारूद को आग देने के लिए कोई भी छोटी सी घटना काफी है।¹¹

भारत ईरान के बीच चाबहार बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है लेकिन अमरीकी प्रतिबंधों के चलते आ रही ढिलाई के कारण चीन का लगातार बढ़ता प्रभाव भारत को लिंक वेस्ट के अभियान में पीछे धकेल रहा है। चीन के लक्ष्य और लक्ष्य में लगभग 200 बिलियन डॉलर के निवेश ने भारत के मुकाबले चीन को बेहतर स्थिति में ला दिया है। इसके अलावा पाक और ईरान के कट्टरपंथी नेताओं में सम्बन्ध अच्छे बन गये तो भारत को बड़ा झटका लग सकता है। अमरीका के 2018 में श्रब्द्धा से बाहर निकलकर ईरान पर लगाये प्रतिबंध भारत को क्षेत्र में पहुँच से बाधित कर रहे हैं।¹²

21 वीं सदी में विश्व की महाशक्तियों के बीच खेले जा रहे इस पश्चिमी एशियाई खेल में भारत को अपना स्थान स्थयं तय करना पड़ेगा। लगातार अस्थिर होती सरकारें, राजशाही शासन व्यवस्था वाले तानाशाही देश और कबीलाई विद्रोहियों के लगातार बढ़ते प्रभाव के त्रिकोण में फंसे पश्चिम एशिया को रूस, अमेरिका और चीन जैसी बड़ी शक्तियों के दाव पेंच ने बड़े संकटग्रस्त क्षेत्र में बदल दिया है। भारत को अब पश्चिम एशियाई देशों को अपनी विदेश नीति की मुख्य प्राथमिकता में लाना होगा तभी भारत के स्थायी राष्ट्रीय हित सुरक्षित हो पायेंगे। भारत के अप्रवासी कामगार, मध्य पूर्व के निवेशकों का महत्वपूर्ण निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, पाकिस्तान पर रणनीतिक दबाव, क्षेत्रीय महाशक्ति के रूप में चीन के

बढ़ते प्रभाव का प्रतिकार कर पाने के विदेश नीति की कुछ विशेष उद्देश्यों सफलता की खातिर नई दिल्ली को पूर्व सक्रिय रूप से सावधानी पूर्वक कदम उठाने होंगे।¹³

भारतीय प्रवासियों के हितों की रक्षा इस अधरज्ञूल वाले माहौल में एक दूरदर्शितापूर्ण एवं स्पष्ट संदेश वाली बहुआयामी विदेश नीति एवं सक्षम कूटनीति के अभाव में कर पाना संभव नहीं है। इसी कारण कतर संकट के दौरान मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। वर्ष 1991 में ईराक में फंसे भारतीयों को एयरलिफ्ट करने के दौरान भी भारतीय अधिकारियों को इसी कारण परेशानी का अनुभव हुआ लेकिन हाल ही के वर्षों में अरब देशों में अस्थिरता के दौरान विदेश राज्य मंत्री वी.के. सिंह द्वारा स्वयं कैम्प कर फंसे हुए भारतीयों को निकालने में सफलता प्राप्त करना बदलती विदेश नीति का परिचायक है।¹⁴

अध्ययन का उद्देश्य

भारत का पड़ोसी देशों के साथ सामाजिक सम्बन्धों को बढ़ाते हुए सामाजिक सम्बन्ध कैसे आगे बढ़ाया जाए प्रथम उद्देश्य है।

निष्कर्ष

इसी तरह सभी बाधाओं के बावजूद भारत के प्रधानमंत्री को सऊदी अरब, फलीस्तीन, इजरायल, यूएई. के सर्वोच्च सम्मान मिलना; खाड़ी देशों के राष्ट्राध्यक्षों के लगातार दौरे, भारतीयों के लिए मंदिरों की जमीनों का आवंटन; अप्रवासियों को संकटग्रस्त क्षेत्रों से निकालने में भारत सरकार की सफलता, अप्रवासियों के हितों की रक्षार्थ सरकार के लगातार किये जा रहे प्रयासों से भारत सरकार की लुक वेस्ट से लिंक वेस्ट की तरफ बढ़ाई गयी पहल की सफलता नजर आती है और भारतीय विदेश नीति में आ रहा यह बदलाव मध्य पूर्व के भारतीय विदेश नीति में बढ़ते महत्व को दर्शाता है।¹⁵

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- www.foreignaffairs.com
- www.meaindia.gov.in
- Thediplomat.com
- www.foreignpolicy.com
- www.journals.sagepub.com
- Indian foreign policy : An overview - harsh v. pant* Manchester university press 2016. P-28
- Indian foreign policy- sumit ganguly oxford press* 2015,P-13
- Modi and the reinvention of I foreign policy -ian haal* policy press 2019,P-56
- Choices : inside the making of India's foreign policy -shivshankar menon penguin UK 2018,P- 10*
- India at risk -Jasvant singh rupa publication* 2013,P-78
- Challenges and strategy : rethinking indians foreign policy -rajiv sikri sage publication 2009,P- 11*
- Hindustan times P-8*
- The hindu 2018,P-9*
- Economic times 2018 ,P-5*
- Dainik bhaskar 2019,P -4*